



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30, 1937

No. 320]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015/VAISAKHA 30, 1937

गृह मंत्रालय

(केन्द्र-राज्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 404(अ).—कैदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा घ (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 01 जनवरी, 2014 को क्रार का अनुसमर्थन करने के बाद, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध 21 मार्च, 2015 से रूसी परिसंघ के लिए लागू होंगे तथा उक्त देश और भारत के बीच कैदियों के अंतरण के लिए भारत गणराज्य सरकार तथा रूसी परिसंघ के बीच की गई संधि के पूर्ण पाठ को निम्नवत अधिसूचित करती है अर्थात् :—

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत-गणराज्य तथा रूसी परिसंघ के बीच संधि

भारत-गणराज्य तथा रूसी परिसंघ, जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकार देश" कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया को सुगम बनाने की अभिलाषा से;

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दण्डित विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश, जहां के वे राष्ट्रिक हैं, में अपनी सज़ा को काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत हो गए हैं:

अनुच्छेद 1

संधि का कार्यक्षेत्र

1. संविदाकार देश इस संधि के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, दण्डित व्यक्तियों के अंतरण से जुड़े मामलों में एक-दूसरे को व्यापक सहायता प्रदान करेंगे।

2. किसी एक संविदाकार देश के भू-भाग में दण्डित किसी व्यक्ति को अधिरोपित दण्ड की सज़ा काटने के लिए इस संधि के उपबंधों के अनुसार अन्य संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए ऐसा व्यक्ति

या उसका विधिक प्रतिनिधि इस संधि के उपबंधों के अनुसार उसके अंतरण के लिए अंतरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश को आवेदन कर सकता है।

3. अंतरण के लिए अनुरोध अंतरणकर्ता देश या प्राप्तकर्ता देश द्वारा किया जा सकता है।

अनुच्छेद 2

परिभाषा

इस संधि के प्रयोजन के लिए :

- 1) "निर्णय" से, किए गए किसी अपराध के लिए दण्ड अधिरोपित करने के संबंध में न्यायालय का अंतिम निर्णय अभिप्रेत है। "निर्णय" शब्द में मृत्यु की सज़ा अधिरोपित करने, जिसे बाद में निर्धारित समयावधि के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने या आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया हो, के संबंध में न्यायालय के अंतिम निर्णय शामिल होंगे;
- 2) "दण्ड" से, दण्डिक न्यायालय के निर्णय द्वारा स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने सहित अधिरोपित कोई दण्ड अभिप्रेत है;
- 3) "दण्डित व्यक्ति" से, दण्ड न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने के रूप में अधिरोपित दण्ड की सज़ा काट रहा व्यक्ति अभिप्रेत है;
- 4) "अंतरणकर्ता देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है, जिसके न्यायालय ने किसी ऐसे व्यक्ति को दण्डित किया है जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो;
- 5) "प्राप्तकर्ता देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो।

अनुच्छेद 3

अंतरण की शर्तें

1. इस संधि के अंतर्गत किसी दण्डित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
 - 1) दण्डित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
 - 2) निर्णय अंतिम हो और उस व्यक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित नहीं हो;
 - 3) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दण्डित व्यक्ति द्वारा सज़ा काटे जाने वाले दण्ड का भाग छह महीने से कम न हो। आपवादिक मामलों में यदि दण्ड की शेष अवधि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से कम हो तो संविदाकार देश अंतरण के बारे में सहमत हो सकते हैं;
 - 4) प्राप्तकर्ता देश के भू-भाग में दण्ड के कार्यान्वयन के लिए दण्डित व्यक्ति के अंतरण के लिए उसके द्वारा लिखित सहमति दी गई हो और आयु, शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में उसकी असमर्थता के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा लिखित सहमति दी गई हो। अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश के कांसूलर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को यह सत्यापित करने का अवसर प्रदान करेगा कि अंतरण के लिए सहमति या अस्वीकृति स्वेच्छा से और ऐसे अंतरण के विधिक परिणामों को समझते हुए दी गई हो;
 - 5) कोई अपराध जिसके लिए दण्ड अधिरोपित किया गया था, प्राप्तकर्ता देश के दण्डिक नियमों के अनुसार स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने से दण्डनीय हो;
 - 6) अंतरणकर्ता देश और प्राप्तकर्ता देश ने अंतरण के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी हो।
2. अंतरण को अस्वीकृत किया जा सकता है यदि :
 - 1) अंतरणकर्ता देश यह समझता हो कि व्यक्ति के अंतरण से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक-व्यवस्था या अन्य अनिवार्य हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
 - 2) दण्डित व्यक्ति को संविदाकार देशों में से किसी एक देश के कानूनों के अनुसार अंतरित नहीं किया जा सकता है;
 - 3) दण्डित व्यक्ति ने न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न किन्हीं वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं किया हो, या यदि अंतरणकर्ता देश की राय में ऐसे दायित्वों को पूरा करने की गारंटियां अपर्याप्त हों;

- 4) दण्डित व्यक्ति पर मृत्यु दण्ड अधिरोपित किया गया हो;
- 5) प्राप्तकर्ता देश में उस देश के कानूनों में निर्धारित कारणों के आधार पर दण्ड को निष्पादित नहीं किया जा सकता हो।

अनुच्छेद 4

केन्द्रीय प्राधिकारी

1. इस संधि के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी केन्द्रीय प्राधिकारी हैं:
भारत गणराज्य के लिए - भारत गणराज्य का गृह मंत्रालय
रूसी परिसंघ के लिए - रूसी परिसंघ का न्याय मंत्रालय
2. इस संधि को कार्यान्वित करते समय, केन्द्रीय प्राधिकारी सीधे संवाद करेंगे।
3. संविदाकार देश, स्वयं से संबंधित केन्द्रीय प्राधिकारी से संबंधी किसी भी परिवर्तन के बारे में दूसरे संविदाकार देश को राजनयिक माध्यम से तत्काल अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 5

सूचना भेजने का दायित्व

1. किसी भी दण्डित व्यक्ति, जिस पर यह संधि लागू होगी, को अन्तरणकर्ता देश इस संधि की विषय-वस्तु तथा ऐसे अन्तरण के विधिक परिणामों के बारे में सूचित करेगा।
2. यदि दण्डित व्यक्ति अपने अन्तरण के लिए अन्तरणकर्ता देश को आवेदन करता है तो उक्त देश अविलंब इसकी सूचना प्राप्तकर्ता देश को देगा।
3. इस प्रकार के नोटिस में निम्नलिखित का उल्लेख होगा:
 - (1) दण्डित व्यक्ति का उपनाम, नाम (कुल नाम), जन्म की तारीख और स्थान, राष्ट्रियता;
 - (2) प्राप्तकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति का स्थायी आवासीय पता, यदि ज्ञात हो, के बारे में सूचना;
 - (3) उन तथ्यों का विवरण, जिन पर दण्ड आधारित था;
 - (4) दण्ड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
 - (5) निर्णय की प्रमाणित प्रति;
 - (6) दण्डित कानूनों के लागू उपबंधों का पाठ;
 - (7) दण्डित व्यक्ति की चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट और अन्य संगत सूचना।
4. यदि दण्डित व्यक्ति उक्त उपबंधों के अनुसरण में अन्तरण के लिए प्राप्तकर्ता देश को आवेदन करता है तो, अन्तरणकर्ता देश अनुरोध किए जाने पर प्राप्तकर्ता देश को इस अनुच्छेद के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सूचना उपलब्ध कराएगा।
5. दण्डित व्यक्ति को पूर्ववर्ती पैराओं के अन्तर्गत प्राप्तकर्ता देश अथवा अन्तरणकर्ता देश द्वारा किसी भी कार्रवाई तथा अन्तरण संबंधी अनुरोध पर किसी भी संविदाकार देश द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 6

अनुरोध एवं प्रत्युत्तर

1. अन्तरण के लिए अनुरोध तथा उनके प्रत्युत्तर लिखित रूप में होंगे और इस संधि के अनुसार नियुक्त केन्द्रीय प्राधिकारियों को अग्रेषित किए जाएंगे।
2. निवेदित देश अन्तरण के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अपने निर्णय के बारे में अनुरोधकर्ता देश को अविलंब सूचित करेगा।

3. अनुरोध में दण्डित व्यक्ति के बारे में सूचना (उपनाम, नाम (कुलनाम), जन्म की तारीख और स्थान) शामिल होगी तथा इसके साथ दण्डित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और उनके स्थायी आवासीय पते को दर्शाने वाले दस्तावेज संलग्न होंगे।
4. अन्तरणकर्ता देश का केन्द्रीय प्राधिकारी अनुरोध के साथ निम्नलिखित को भी संलग्न करेगा :
 - 1) निर्णय तथा न्यायालय के सभी संगत निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां और दस्तावेज, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि यह निर्णय अंतिम है;
 - 2) स्वतंत्रता से वंचित रहने के रूप में भोगा गया दण्ड तथा दण्ड का वह भाग जो भोगा जाना शेष है, के साथ निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित दस्तावेज तथा दण्ड भोगने के दौरान दण्डित व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाने वाला एक दस्तावेज;
 - 3) दण्डित कानून के उन उपबंधों का पाठ जिनके आधार पर व्यक्ति को दण्ड दिया गया था;
 - 4) प्राप्तकर्ता देश के भू-भाग में दण्ड के निष्पादन के लिए अपने अंतरण हेतु दण्डित व्यक्ति की लिखित सहमति और यदि वह अपनी आयु, शारीरिक या मानसिक अवस्था के कारण स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा प्रकट करने में असमर्थ हो तो उसके कानूनी प्रतिनिधि की लिखित सहमति;
 - 5) दण्डित व्यक्तियों पर निर्णय द्वारा लगाए गए वित्तीय भार को दर्शाने वाला दस्तावेज;
 - 6) दण्डित व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति तथा प्राप्तकर्ता देश के भू-भाग में अन्तरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्ति की सक्षमता के बारे में रिपोर्ट।
5. अन्तरण संबंधी अनुरोध पर सहमत होने की स्थिति में प्राप्तकर्ता देश का केन्द्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित सूचना देगा :
 - (1) शेष सजा काटने के लिए दण्डित व्यक्ति को स्वीकार करने हेतु लिखित सहमति;
 - (2) दण्डित व्यक्ति के अंतरण के पश्चात् प्राप्तकर्ता देश में दण्ड की अवधि और प्रवर्तन से संबंधित लागू कानूनों के बारे में न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय की अधिप्रमाणित प्रति;
 - (3) उन कानूनों से प्रमाणित उद्धरण जिनके आधार पर दण्डित व्यक्ति सजा काटेगा;
 - (4) दण्डित व्यक्ति की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने संबंधी दस्तावेज।
6. यदि आवश्यक हो तो, संविदाकार देशों के केन्द्रीय प्राधिकारी किन्हीं अतिरिक्त दस्तावेजों अथवा सूचना के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

अनुच्छेद 7

व्यय

अभिवहन पर होने वाले व्यय सहित दण्डित व्यक्ति के अंतरण पर होने वाले व्यय, अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे।

अनुच्छेद 8

अन्तरण की प्रक्रिया

1. सभी आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी संविदाकार देश का केन्द्रीय प्राधिकारी दूसरे संविदाकार देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को, इस संधि के निबंधन और शर्तों के अधीन, दण्डित व्यक्ति के अंतरण अथवा उसे स्वीकार करने के संबंध में अपनी सहमति/अस्वीकृति के बारे में तुरंत सूचित करेगा।
2. संविदाकार देशों के केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा दण्डित व्यक्ति के अंतरण के स्थान समय और प्रक्रिया का तुरंत निर्धारण किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

दण्ड का प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता देश, अपने कानूनों के अनुसार दण्ड, के प्रवर्तन की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा और वह अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा अवधारित दण्ड की विधिक प्रकृति और अवधि से आवद्ध होगा।

2. अंतरणकर्ता देश के निर्णय के आधार पर प्राप्तकर्ता देश का न्यायालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी, अपने देश के कानूनों के अध्यक्षीन तथा उसके अनुसार, यथासंभव उतने कारावास की अवधि का ही दण्ड देगा जो उस निर्णय में दी गई हो और दण्ड में वृद्धि नहीं करेगा।

यदि, प्राप्तकर्ता देश के कानूनों के अनुसार, किए गए अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि उस निर्णय में उल्लिखित अवधि से कम हो तो प्राप्तकर्ता देश का न्यायालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी उसी अपराध को करने के लिए प्राप्तकर्ता देश के कानूनों में उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि का दण्ड देगा।

3. अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में काटी गई सज़ा की अवधि को दण्ड की कुल अवधि में से कम कर दिया जाएगा।

4. उक्त निर्णय में स्वतंत्रता से वंचित किए जाने सहित दिए गए किसी अन्य दण्ड को प्रवर्तित करने के बारे में निर्णय प्राप्तकर्ता देश के न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा यदि किए गए अपराध के लिए उस देश के कानून में इस प्रकार के दण्ड की व्यवस्था हो।

अनुच्छेद 10

क्षमा, राजक्षमा, दण्ड का लघुकरण और निर्णय की समीक्षा

1. कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप क्षमा, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा और दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

2. केवल अंतरणकर्ता देश ही किसी अपील अथवा निर्णय की पुनरीक्षा का निर्णय लेगा।

अनुच्छेद 11

दो बार दण्डित न किया जाना

अंतरण के उपरांत, दण्डित व्यक्ति पर प्राप्तकर्ता देश में उन्हीं आपराधिक कृत्यों, जिनके लिए उसे अंतरणकर्ता देश द्वारा दण्डित किया जा चुका है, के विरुद्ध मुकदमा अथवा कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 12

संशोधन एवं दण्ड के प्रवर्तन का समापन

1. अंतरणकर्ता देश ऐसे किसी भी निर्णय, जो सज़ा के प्रवर्तन में संशोधन अथवा समापन के लिए अपरिहार्य हो, के बारे में प्राप्तकर्ता देश को तुरंत सूचित करेगा।

2. अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी संगत निर्णय के बारे में जैसे ही सूचित किया जाएगा, प्राप्तकर्ता देश सजा अथवा उसके किसी भाग के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 13

निर्णय का संशोधन एवं माफी

1. यदि, सज़ा काटने के लिए दण्डित व्यक्ति के अंतरण के बाद, अंतरणकर्ता देश के न्यायालय द्वारा निर्णय में संशोधन किया जाता है, तो निर्णय की एक प्रति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तुरंत प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सौंपे जाएंगे। प्राप्तकर्ता देश, इस संधि के अनुच्छेद 9 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्णय के प्रवर्तन के मुद्दे का समाधान करेगा।

2. यदि, सजा काटने के लिए दण्डित व्यक्ति के अंतरण के बाद, अंतरणकर्ता देश में सज़ा माफ की जाती है, तो निर्णय की प्रति तत्काल प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सौंपी जाएगी।

अनुच्छेद 14

सूचना का आदान-प्रदान

1. सज़ा के प्रवर्तन, क्षमा, राजक्षमा अथवा पैरोल प्रदान करने तथा दण्डित व्यक्ति के भाग जाने अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में प्राप्तकर्ता देश का केन्द्रीय प्राधिकारी अंतरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।

2. अंतरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के अनुरोध पर प्राप्तकर्ता देश का केन्द्रीय प्राधिकारी दण्डित व्यक्ति के अंतरण के बाद सज़ा भुगतने की प्रक्रिया के बारे में सूचना मुहैया कराएगा।

3. जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा हो गया हो तो प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को भी सूचित करेगा।

अनुच्छेद 15**अभिवहन**

1. कोई संविदाकार देश अपने कानून के अनुसार अपने भू-भाग के जरिए दण्डित व्यक्ति के अभिवहन के लिए किए गए अनुरोध को मानेगा यदि उस व्यक्ति के अंतरण के लिए दूसरे संविदाकार देश द्वारा यह अनुरोध किया गया हो, जो तीसरे देश को मंजूर हो।
2. कोई संविदाकार देश अभिवहन की अनुमति देने से मना कर सकता है यदि:
 - (1) दण्डित व्यक्ति उसका अपना राष्ट्रिक हो;
 - (2) वह अपराध, जिसके लिए दण्ड लगाया गया है, इसके कानून के अंतर्गत ऐसा नहीं समझा गया हो।
3. अभिवहन के अनुरोध में अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट सूचना शामिल होगी और इसके साथ इस संधि के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 1 तथा पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ "1" और "3" में विनिर्दिष्ट दस्तावेज भेजे जाएंगे।
4. अभिवहन की अनुमति के लिए प्रार्थित संविदाकार देश दण्डित व्यक्ति को केवल इसके भू-भाग से होकर अभिवहन हेतु अपेक्षित अवधि के लिए अपनी हिरासत में रख सकता है।
5. अभिवहन के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है, यदि अभिवहन हवाई जहाज द्वारा किया जाता है और दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग पर इसे उतारने की संभावना नहीं है। फिर भी, उस संविदाकार देश को उसके भू-भाग के ऊपर से ऐसे किसी अभिवहन के बारे में अधिसूचित करना होगा।

अनुच्छेद 16**भाषा**

अनुरोध तथा समर्थनकारी दस्तावेज, अधिसूचनाएं और सूचना अनुरोधकर्ता संविदाकार देश की भाषा में होंगी तथा इनके साथ निवेदित संविदाकार देश की भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भेजा जाएगा और ये किसी वैधीकरण के अध्यधीन नहीं होंगे।

अनुच्छेद 17**लागू किए जाने का दायरा**

यह संधि, इसके प्रभावी होने से पहले और उसके बाद लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन के संबंध में लागू होगी।

अनुच्छेद 18**विवादों का निपटारा**

इस संधि की व्याख्या और कार्यान्वयन के बारे में संविदाकार देशों के बीच पैदा हुए किन्हीं विवादों का निपटारा संविदाकार देशों के केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा परामर्श और बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 19**संधि में संशोधन**

इस संधि में, संविदाकार देशों की पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 20**अंतिम प्रावधान**

1. यह संधि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी। यह संधि इसकी शुरुआत के लिए यथा अपेक्षित सभी आंतरिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर राजनयिक माध्यमों से संविदाकार देशों के अंतिम लिखित नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के पश्चात् बाध्यकारी होगी।
2. यह संधि किसी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को राजनयिक माध्यम से इसे समाप्त करने के अपने आशय के लिखित नोटिस देने की तारीख के 180 दिन के पश्चात् समाप्त हो जाएगी।

3. इस संधि के समापन की तारीख से पूर्व प्राप्त अंतरण के अनुरोध को अंतिम रूप दिए जाने में कोई अवरोध नहीं होगा।

4. इस समापन के बावजूद, इस संधि के उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू रहेंगे जिनको इस संधि के अनुसार पहले ही अंतरित किया जा चुका है।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते, इसे मॉस्को में 21 अक्टूबर, 2013 को अंग्रेजी, हिन्दी और रूसी भाषाओं में दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में विसंगति होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की ओर से

रूसी परिसंघ की ओर से

[फा. सं. वी-17011/7/2010-पी आर]

कुमार आलोक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2015

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections d(1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government having ratified the Agreement on the 01st January, 2014, hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Russian Federation with effect from the 21st March, 2015, and notifies the full text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Russian Federation for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :—

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE RUSSIAN FEDERATION ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

THE REPUBLIC OF INDIA and THE RUSSIAN FEDERATION, hereinafter referred to as the “Contracting States”,

ASPIRING to facilitate the process of social rehabilitation of sentenced persons,

CONSIDERING that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their country of nationality;

HEREBY have agreed as follows:

Article 1

Scope of the Treaty

1. The Contracting States shall, in accordance with the terms and conditions of this Treaty, provide each other with the widest measure of assistance in matters related to transfer of sentenced persons.

2. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Treaty in order to serve the sentence imposed. For that end such person or his/her legal representative may apply to either Transferring State or Receiving State for his/her transfer in accordance with the provisions of this Treaty.

3. The request for transfer may be submitted by either Transferring State or Receiving State.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Treaty, the following terms shall mean:

- (1) “judgement” – a final court decision imposing sentence for a crime committed. The term “judgement” shall also include final court decisions imposing death penalty, later substituted for a fixed term of deprivation of liberty or for life imprisonment in Transferring State;

- (2) “sentence” – any punishment including deprivation of liberty, imposed by judgement of criminal court;
- (3) “sentenced person” – a person serving a sentence in the form of deprivation of liberty, imposed by a judgement of criminal court;
- (4) “Transferring State” – a State, The court of which has sentenced a person that may be transferred or has been transferred;
- (5) “Receiving State” – a State, to which the sentenced person may be transferred or has been transferred in order to serve the sentence.

Article 3

Conditions for Transfer

1. A sentenced person may be transferred under this Treaty only on the following conditions:
 - (1) the sentenced person is a national of the Receiving State ;
 - (2) the judgement is final, and there are no proceedings pending in respect of this person;
 - (3) at the time of receipt of request for transfer, the part of sentence to be served by the sentenced person is not less than six months. In exceptional cases, the Contracting States may agree on transfer if the remaining term of sentence is less than that specified above;
 - (4) there is a written consent by the sentenced person for his/her transfer for execution of sentence in the territory of the Receiving State and in case of his/her inability to freely express his/her will due to age, physical or mental condition – a written consent by his/her legal representative. The Transferring State shall provide a consular officer or any other official of the Receiving State with an opportunity to verify that the consent for transfer or rejection thereof was given voluntarily and with understanding of legal consequences of such transfer;
 - (5) the crime for which the sentence was imposed are punishable by deprivation of liberty according to criminal laws of the Receiving State;
 - (6) Transferring State and Receiving State have clearly given their consent for transfer.
2. The transfer may be rejected if:
 - (1) the Transferring State considers that transfer of the person would impair its sovereignty, security, public order or other essential interests;
 - (2) the sentenced person cannot be transferred according to the law of either of the Contracting States;
 - (3) the sentenced person has not fulfilled any financial obligations arising from a court judgement, or if, in the opinion of Transferring State, the guarantees of fulfillment of such obligations are insufficient;
 - (4) the death sentence has been imposed on the sentenced person;
 - (5) the sentence cannot be executed in the Receiving State due to reasons stipulated in the laws of such State.

Article 4

Central Authorities

1. The Central Authorities in charge of the implementation of this Treaty are:

For the Republic of India – Ministry of Home Affairs of the Republic of India.

For the Russian Federation – Ministry of Justice of the Russian Federation.
2. When implementing this Treaty, the Central Authorities shall communicate directly.
3. The Contracting State shall immediately notify the other Contracting State of any changes connected with its respective Central Authority through diplomatic channels.

Article 5

Obligation to Provide Information

1. Any sentenced person to whom this Treaty may be applied shall be informed by the Transferring State of the contents of this Treaty as well as of legal consequences of such transfer.
2. If the sentenced person applies to the Transferring State for his/her transfer, that State shall promptly inform the Receiving State.
3. Such notice shall include:
 - (1) surname, name (patronymic), date and place of birth, nationality of the sentenced person;
 - (2) information about permanent place of residence of the sentenced person in the Receiving state, if known;
 - (3) a statement of the facts, upon which the sentence was based;
 - (4) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
 - (5) a certified copy of the judgement;
 - (6) the text of applicable provisions of the criminal laws;
 - (7) report of the medical condition of the sentenced person and other relevant information.
4. If the sentenced person applies to the Receiving State for transfer pursuant to the provisions hereof, the Transferring State shall provide the Receiving State on request with the information specified in paragraph 3 of this Article.
5. The sentenced person shall be informed in writing of any action taken by the Receiving State or by the Transferring State under the preceding paragraphs as well as of any decision taken by either of The Contracting States on request for transfer.

Article 6

Requests and Responses

1. Requests for transfer and responses to them shall be made in writing and forwarded to the Central Authorities appointed in accordance with this Treaty.
2. The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its decision to accept or reject the request of transfer.
3. The request shall contain information about the sentenced person (surname, name (patronymic), date and place of birth), and shall be accompanied by the documents indicating the nationality of the sentenced person and his/her permanent place of residence.
4. The Central Authority of the Transferring State shall also accompany the request with:
 - 1) certified copies of the judgement and all relevant court decisions and a document confirming that the judgment has become final;
 - 2) the document pertaining to enforcement of the judgement including the part of sentence served in the form of deprivation of liberty and the part of sentence to be served as well as the document indicating sentenced person's behavior while serving the sentence;
 - 3) the text of provisions of the criminal law on account of which the person was sentenced;
 - 4) a written consent of the sentenced person for his/her transfer for execution of a sentence in the territory of the Receiving State and in case of his/her inability to freely express his/her will due to age, physical or mental condition – a written consent of his/her legal representative;
 - 5) The document indicating the financial implications imposed by the judgement on the sentenced persons;
 - 6) A report on the medical condition of the sentenced person and on the ability of the sentenced person to be transferred to the territory of the Receiving State.

5. The Central Authority of the Receiving State in case of agreeing to the transfer request, may provide the following information:-

- (1) a written consent to receive the sentenced person to serve the remaining sentence;
- (2) authenticated copy of decision by the court or any other Competent Authority regarding applicable laws relating to the duration and enforcement of sentence in the Receiving State after the sentenced persons transfer;
- (3) certified extracts from the laws on the basis of which the sentenced person will serve the sentence;
- (4) a document confirming the nationality of the sentenced person.

6. If necessary, the Central Authorities of the Contracting States may request any additional documents or information.

Article 7

Expenses

Expenses incurred in the transfer of the sentenced person, including the expenses on transit, shall be borne by the Receiving State, except expenses incurred in the territory of the Transferring State.

Article 8

Procedure of Transfer

1. The Central Authority of either Contracting State after receipt of all necessary documents shall promptly inform the Central Authority of the other Contracting State of its consent/rejection to transfer or receive the sentenced person, subject to the terms and conditions of this Treaty.

2. Place, time and procedure of transfer of the sentenced person shall promptly be determined by the Central Authorities of the Contracting States.

Article 9

Enforcement of Sentence

1. The Receiving State shall ensure the continuing of enforcement of sentence in accordance with its laws and is bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Transferring State.

2. The court or any other competent authority of the Receiving State, on the basis of the judgement of the Transferring State, shall, subject to and in accordance with the laws of its State, impose the same term of imprisonment as far as possible as that imposed in the judgement and shall not aggravate the sentence.

If, according to the laws of the Receiving State, the maximum term of imprisonment for the crime committed is less than that imposed by the judgement, the court or any other competent authority of the Receiving State shall impose the maximum term of imprisonment provided for by the laws of the Receiving State for committing the same crime.

3. The part of the sentence served in the territory of the Transferring State shall be deducted from the total term of the sentence.

4. Decision on enforcing any other punishment along with deprivation of liberty imposed by the judgement shall be taken by the court or any other competent authority of the Receiving State, if such punishment for the crime committed is provided for by the laws of such State.

Article 10

Pardon, Amnesty, Commutation of Sentence and Review of Judgement

1. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of sentence in accordance with its Constitution or other laws.

2. Only the Transferring State shall have the jurisdiction to decide an appeal or review of the judgement.

ARTICLE 11**Non bis in idem**

After transfer, the sentenced person shall not be prosecuted or proceeded against in Receiving State for the Same Criminal acts as the ones pon account of which the sentence was imposed in the Transferring State.

Article 12**Modification and Termination of Enforcement of Sentence**

1. The Transferring State shall promptly notify the Receiving State of any decision which entail modification or termination of the enforcement of sentence.

2. The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the Transferring State of any relevant decision.

Article 13**Revision and Remission of Judgement**

1. If, after the transfer of the sentenced person for serving the sentence, the judgement is revised by the court of the Transferring State, a copy of the judgement and other necessary documents shall be promptly submitted to the Central Authority of the Receiving State. The Receiving State shall resolve the issue of enforcing such decision as specified in Article 9 of this Treaty.

2. If, after the transfer of the sentenced person for serving the sentence, the sentence is remitted in the Transferring state, a copy of the decision shall be promptly submitted to the Central Authority of the Receiving State.

Article 14**Exchange of Information**

1. The Central Authority of the Receiving State shall inform the Central Authority of the Transferring State of the decision taken by a court or competent authority in order to enforce the sentence, of granting pardon, amnesty or parole and in case of escape or death of the sentenced person.

2. The Central Authority of the Receiving State on request of the Central Authority of the Transferring State shall provide information on the process of serving the sentence after the sentenced person's transfer.

3. The Receiving State shall also inform the Transferring State when the enforcement of the sentence has been completed.

Article 15**Transit**

1. A Contracting State shall in accordance with its law satisfy a request for transit of a sentenced person through its territory if such request is made by the other Contracting State, which has agreed with a third State to the transfer of that person.

2. A Contracting State may refuse to permit transit if:

- 1) the sentenced person is its national;
- 2) the crime for which the sentence was imposed is not considered as such under its law.

3. The request for transit shall include the information specified in Paragraph 3 of Article 6 and shall be accompanied by the documents specified in Paragraph 1 and subparagraphs "1" and "3" of Paragraph 4 of Article 6 of this Treaty.

4. The Contracting State requested to permit transit may hold the sentenced person in custody only for such time as transit through its territory requires.

5. A request for transit is not required if such transit is carried out by air and no landing in the territory of the other Contracting State is expected. However, that Contracting State has to be notified of any such transit over its territory.

Article 16

Languages

The request and supporting documents, notifications and information shall be in the language of the requesting Contracting State and shall be accompanied with translation into the language of the requested Contracting State or into the English language and shall not be subject to legalization .

Article 17

Temporal Application

This Treaty shall be applicable to enforcement of sentences imposed both before and after its entry into force.

Article 18

Settlement of Disputes

Any disputes, arising between the Contracting States regarding interpretation and implementation of this Treaty, shall be settled through consultations and negotiations by the Central Authorities of the Contracting States.

Article 19

Amendments to the Treaty

This Treaty may be amended by mutual consensus of the Contracting States.

Article 20

Final Provisions

1. This Treaty shall remain in force for an indefinite period of time. The Treaty becomes binding upon expiry of 30 days from the date of receipt of the last written notice from the Contracting States through diplomatic channels on completion of all internal procedures as required for its commencement.

2. This Treaty terminates upon expiry of 180 days from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it through diplomatic channels.

3. The termination of this Treaty shall not impede finalization of requests for transfer, received prior to the date of termination.

4. Notwithstanding any termination, the provisions of this treaty shall continue to apply to persons who have already been transferred in accordance with this Treaty.

Done in Moscow this 21st day of October 2013 in duplicate, each in English, Hindi and Russian languages, all texts being equally authentic. In case of discrepancies in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of India

For the Russian Federation

[F. No. V-17011/7/2010-PR]

KUMAR ALOK, Jt. Secy.